नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 207
दि. 01.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कहा-इच्छा के विरुद्ध मातृत्व नहीं थोपा जा सकता

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था Supreme Court of India ने एक बेहद संवेदनशील और जटिल मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने इस मामले में दायर क्यूरेटिव याचिका पर गंभीर आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध मातृत्व के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने न केवल न्यायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है, बल्कि देश में गर्भपात कानूनों पर भी एक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह माना कि यह एक बाल दुष्कर्म का मामला है, जिसमें पीड़िता पहले ही गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात से गुजर चुकी है। यदि उसे इस स्थिति में गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी और गंभीर प्रभाव डाल सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी सीमाओं को नहीं, बल्कि मानवीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अदालत ने केंद्र सरकार को यह सुझाव भी दिया कि वह वर्तमान कानून में संशोधन पर विचार करे, ताकि दुष्कर्म पीड़िताओं को 20 सप्ताह की समय सीमा के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जा सके। अदालत का मानना है कि जब गर्भधारण अपराध का परिणाम हो, तो समय सीमा जैसी बाधाएं पीड़िता के अधिकारों के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। यह टिप्पणी देश के मौजूदा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) कानून की सीमाओं की ओर इशारा करती है, जो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गर्भपात की अधिकतम

अवधि तय करता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि गर्भपात से पीड़िता को स्थायी शारीरिक नुकसान नहीं होता है, तो चिकित्सा दृष्टि से इसे किया जाना चाहिए। साथ ही All India Institute of Medical Sciences को निर्देश दिया गया कि वह पीड़िता और उसके माता-पिता को पूरी जानकारी और परामर्श प्रदान करे, ताकि वे सूचित और समझदारी भरा निर्णय ले सकें। अदालत ने यह भी दोहराया कि अंतिम निर्णय पीड़िता और उसके परिवार का होना चाहिए, क्योंकि वही इस स्थिति के वास्तविक प्रभावों को समझ सकते हैं। इस मामले में AIIMS की ओर से पेश की गई दलीलों पर भी अदालत ने विचार किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि 30 सप्ताह की गर्भावस्था में भ्रूण एक विकसित अवस्था में होता है और इस समय गर्भपात कराना चिकित्सकीय रूप से जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे नाबालिग मां के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है और भविष्य में उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को जन्म के बाद गोद देने का विकल्प अपनाया जा सकता है।

हालांकि अदालत ने इन दलीलों को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तत्व पीड़िता की इच्छा और उसका मानसिक स्वास्थ्य है। अदालत ने कहा कि एक नाबालिग, जो पहले ही यौन हिंसा का शिकार हो चुकी है, उसे एक अनचाही गर्भावस्था ढोने के लिए मजबूर करना न्यायसंगत नहीं होगा। यह उसके जीवन, शिक्षा और भविष्य के अधिकारों के साथ अन्याय होगा।

अदालत ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। उसने कहा कि देश में पहले से ही कई बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें गोद लेने के लिए परिवार नहीं मिलते और वे बेसहारा जीवन जी रहे हैं। ऐसे में केवल इस आधार पर कि बच्चे को जन्म देकर गोद दिया जा सकता है, किसी पीड़िता को मातृत्व के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है।

मीडिया की भूमिका को लेकर भी अदालत ने विशेष टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया से अपील की कि इस तरह के संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय संयम और जिम्मेदारी का परिचय दिया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत में हुई हर बातचीत को सार्वजनिक करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पीड़िता की निजता और गरिमा प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले 24 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अदालत ने तब कहा था कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उस समय अदालत ने यह भी ध्यान में रखा था कि पीड़िता ने पहले दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था, जो उसके मानसिक तनाव की गंभीरता को दर्शाता है। ऐसे में गर्भावस्था को जारी रखना उसके हित में नहीं माना गया।

इस पूरे मामले ने देश में गर्भपात के अधिकार, महिलाओं की स्वायत्तता और कानून की सीमाओं पर एक गहन चर्चा को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है, जहाँ न्यायालय को कानूनी प्रावधानों और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाना होता है।

अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह रुख यह स्पष्ट करता है कि न्याय केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे पहलुओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। यह फैसला न केवल एक पीड़िता के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज को भी यह संदेश देता है कि संवेदनशीलता और सहानुभूति के बिना न्याय अधूरा है।

री-पोल की मांग से गरमाई सियासत: 77 बूथों पर शिकायतों की गहन जांच में जुटा चुनाव आयोग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद 77 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग ने राजनीतिक माहौल को एक बार फिर गरमा दिया है। विभिन्न दलों और उम्मीदवारों की ओर से उठाए गए आरोपों के बाद Election Commission of India ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और बिना ठोस जांच के कोई भी निर्णय नहीं किया जाएगा। आयोग ने संकेत दिए हैं कि यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो संबंधित बूथों पर पुनर्मतदान कराने से भी परहेज नहीं किया जाएगा।

दक्षिण 24 परगना जिले की चार विधानसभा सीटों से बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आई हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। इनमें सबसे अधिक शिकायतें फालता विधानसभा क्षेत्र से दर्ज की गई हैं, जहाँ 32 बूथों को लेकर पुनर्मतदान की मांग उठी है। इसके अलावा डायमंड हार्बर से 29, मगराहाट से 13 और बजबज से 3 शिकायतें आयोग के पास पहुँची हैं। कुल मिलाकर 77 बूथों पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई है। इन शिकायतों में कई गंभीर आरोप शामिल हैं। कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है, यहाँ तक कि मशीनों पर किसी प्रकार का पदार्थ डालने की बात भी कही गई है। इसके अलावा निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों को बाधित करने और उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करने के आरोप भी सामने आए हैं। कई शिकायतों में यह भी कहा गया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। कुछ बूथों पर मतदान की गोपनीयता भंग होने के आरोप भी लगाए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माने जाते हैं।

चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar ने विशेष पर्यवेक्षक सुभ्रत गुप्ता को मौके पर जाकर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार हर प्रभावित बूथ का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। इसके साथ ही अन्य नियुक्त पर्यवेक्षकों से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।

आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह केवल औपचारिक जांच नहीं है, बल्कि हर शिकायत को तथ्यात्मक रूप से परखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, मतदान रिकॉर्ड, और संबंधित अधिकारियों के बयान भी जांच का हिस्सा बनाए गए हैं। यदि किसी भी बूथ पर अनियमितता या नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पुनर्मतदान भी शामिल है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मामला बेहद अहम हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा से ही उच्च प्रतिस्पर्धा और तीखी राजनीतिक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में पुनर्मतदान की मांग ने विभिन्न दलों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने का अवसर दे दिया है। विपक्षी दल जहां चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बता सकता है। इससे चुनावी माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी है। एक ओर उसे निष्पक्षता बनाए रखनी है, वहीं दूसरी ओर जनता का विश्वास भी कायम रखना है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई ही आयोग की विश्वसनीयता को मजबूत कर सकती है।

आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी, तो प्रभावित बूथों पर जल्द ही दोबारा मतदान कराया जा सकता है। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्णय से पहले सभी तथ्यों और सबूतों का गहन विश्लेषण किया जाएगा, ताकि कोई भी कदम पूरी तरह न्यायसंगत और निष्पक्ष हो।

फिलहाल पूरे राज्य की नजरें चुनाव आयोग की इस जांच पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में इन 77 बूथों पर अनियमितताएं हुई थीं या यह केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा है। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य को और अधिक संवेदनशील और रोचक बना दिया है।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर विराम: खरगे ने अटकलों को किया खारिज, फिलहाल सीएम बदलने का सवाल नहीं

बंगलूरू। कर्नाटक की राजनीति में पिछले कुछ समय से चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके इस बयान से उन तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में सत्ता का संतुलन बदल सकता है और नेतृत्व में फेरबदल संभव है।

खरगे का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य की सियासत में अंदरखाने काफी हलचल देखने को मिल रही थी। खासकर उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इन अटकलों को उस समय और बल मिला, जब डीके शिवकुमार और उनके भाई DK Suresh ने हाल ही में दिल्ली जाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थीं कि कर्नाटक में सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं।

हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में किसी भी तरह का नेतृत्व संकट नहीं है और सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि कोई आंतरिक मुद्दा है, तो उसे पार्टी के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा और सार्वजनिक रूप से इस पर अनावश्यक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उनका यह रुख पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने और अनिश्चितता को खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

कर्नाटक में मौजूदा समय में Siddaramaiah मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि चुनाव के दौरान सत्ता साझा करने को लेकर कोई समझौता हुआ था, जिसके तहत एक निश्चित अवधि के बाद नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस तरह के किसी भी समझौते की आधिकारिक पुष्टि न तो पार्टी नेतृत्व ने की है और न ही संबंधित नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया है।

खरगे के बयान से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कांग्रेस फिलहाल किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन के मूड में नहीं है और वह स्थिरता बनाए रखना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है that इस समय पार्टी किसी भी तरह के अंदरूनी बदलाव से बचना चाहती है, खासकर तब जब राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण चुनावी परिणाम सामने आने वाले हैं। 4 मई को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं, और इसके बाद ही पार्टी बड़े राजनीतिक फैसले लेने की स्थिति में हो सकती है।

इस बीच, डीके शिवकुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थीं, वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पार्टी के भीतर उनकी भूमिका और महत्व को लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी दावेदारी पर अब तत्काल कोई निर्णय होता नहीं दिख रहा। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अपने पद पर कायम हैं और सरकार के कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं।

राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे को बेहद सावधानी से संभाल रहा है, ताकि किसी भी तरह की आंतरिक कलह सार्वजनिक न हो और पार्टी की छवि पर असर न पड़े। कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ की स्थिरता पार्टी के राष्ट्रीय समीकरणों पर भी प्रभाव डाल सकती है।

फिलहाल, खरगे के स्पष्ट और दोटूक बयान ने यह साफ कर दिया है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं अभी केवल अटकलों तक ही सीमित हैं। आने वाले समय में राजनीतिक परिस्थितियाँ किस दिशा में जाती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य में स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्योंझर कंकाल प्रकरण: शुरुआती जांच में बैंक की लापरवाही उजागर, जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत

क्योंझर। ओडिशा के चर्चित "कंकाल प्रकरण" ने प्रशासन और बैंकिंग व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि पूरे घटनाक्रम में बैंक की लापरवाही एक प्रमुख कारण रही। अधिकारियों ने साफ किया है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता और आम लोगों की समझ के बीच की खाई को भी उजागर किया है।

घटना उस समय सामने आई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें करीब 50 वर्षीय जीतू मुंडा अपनी मृत बहन के कंकाल को कंधे पर उठाकर बैंक की शाखा तक ले जाते हुए दिखाई दिए। यह दृश्य न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि आखिर किन परिस्थितियों ने एक व्यक्ति को इस हद तक जाने के लिए मजबूर किया। बताया गया कि वह अपनी दिवंगत बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए ऐसा करने को विवश हुए।

इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार हरकत में आई और मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi ने तत्काल जांच के आदेश दिए। उन्होंने उत्तरी मंडल के राजस्व संभागीय आयुक्त को पूरे मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रशासनिक टीम सक्रिय हुई और जांच के लिए संबंधित

बैंक शाखा का दौरा किया गया।

जांच के दौरान अधिकारियों की टीम, जिसमें उत्तरी मंडल के आरडीसी संग्राम केशरी महापात्रा और क्योंझर जिले के आयुक्त विशाल सिंह शामिल थे, Odisha Gramya Bank की मालीपोसी शाखा पहुँची। यहाँ उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और बैंक कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ की। अधिकारियों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी मृत बहन के कंकाल के साथ बैंक जाना पड़ा।

प्रारंभिक जांच के बाद आरडीसी संग्राम केशरी महापात्रा ने बताया कि इस पूरे मामले में बैंक की भूमिका संदिग्ध और लापरवाही भरी प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि "प्रथम दृष्टया यह बैंक की गलती लगती है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने यह भी बताया कि जीतू मुंडा और उनकी बहन पहले भी कई बार बैंक गए थे और उन्होंने खाते से पैसे निकाले थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई पहली बार का लेन-देन नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि जीतू मुंडा पूरी तरह अनपढ़ नहीं हैं, लेकिन उन्हें बैंकिंग प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं है। यह एक अहम बिंदु है, क्योंकि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कई लोग बैंकिंग नियमों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह परिचित नहीं होते। ऐसे में बैंक कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि वे ग्राहकों को सही मार्गदर्शन दें और उनकी मदद करें। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिससे स्थिति इतनी गंभीर हो गई। सूत्रों के अनुसार, बैंक कर्मचारियों ने न तो उचित सहयोग किया और न ही मानवीय संवेदनशीलता दिखाई। यदि समय पर सही जानकारी और सहायता दी जाती, तो शायद यह घटना इस रूप में सामने नहीं आती। इस घटना ने यह भी दिखाया कि सरकारी और बैंकिंग संस्थाओं में संवेदनशीलता और जवाबदेही की कितनी आवश्यकता है।

यह मामला केवल एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है, जहाँ सिस्टम की जटिलता आम आदमी के लिए कठिनाइयाँ पैदा करती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ लोग अक्सर दस्तावेजों, प्रक्रियाओं और नियमों से अनजान होते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएँ अधिक गंभीर रूप ले सकती हैं। राज्य सरकार ने इस मामले को उदाहरण बनाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इसमें बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और ग्रामीण ग्राहकों को जागरूक करने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस घटना ने पूरे राज्य में एक बहस छेड़ दी है—क्या हमारी संस्थाएं आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप काम कर रही हैं? क्या नियमों का पालन करते हुए मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन इतना तय है कि क्योंझर का यह कंकाल प्रकरण लंबे समय तक लोगों के जेहन में बना रहेगा और यह प्रशासन तथा बैंकिंग तंत्र के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा।

संपादकीय

गहन चिकित्सा देखभाल के संवेदनशील दिशानिर्देश

अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि देश के किसी भाग में किसी निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज के ठीक होने या ठीक होने की संभावना के बावजूद उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। वजह होती है कि अस्पताल का अनवरत गति से चलने वाला कमाई का मीटर। निस्संदेह, आधुनिक चिकित्सा खर्चीली हो गई और बेहतर सुविधाओं के लिए बड़ी रकम चुकानी होती है। लेकिन इस व्यवस्था का मानवीय व संवेदनशील होना अपरिहार्य है। इसके नियमन का कार्य यूं तो देश के नीति-नियंताओं और शासन-प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन विडंबना यह है कि अदालत को ऐसे मामलों में पहल करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान गहन चिकित्सा ईकाई दिशानिर्देशों की जरूरत बताना विसंगतियों से जूझती आईसीयू प्रणाली के लिए एक आशा की किरण लेकर आई है। इन दिशानिर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके या जिन मरीजों के अंगों को बाहरी सहायता अथवा शारीरिक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। उन्हें अन्य सामान्य वार्डों में स्थानांतरित किया जा सकता है। निश्चित रूप से न्यायालय के ये निर्देश चिकित्सकीय और नैतिक दोनों ही हैं। जो बताते हैं कि जरूरी न होने के बावजूद मरीज को लंबे समय तक आईसीयू में रखना अनुचित है। यह एक हकीकत है कि मानकीकृत आईसीयू प्रोटोकॉल के अभाव में एक अस्पष्ट स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज से जुड़े निर्णय असमंजस का शिकार होकर रह जाते हैं। वास्तव में आईसीयू में भर्ती मरीजों के तिमारदारों को चिकित्सा प्रक्रिया की गहन जानकारी अक्सर नहीं होती है। वे केवल चिकित्सक के दिशा-निर्देशों पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन के रहमो-करम पर मरीज को महंगे आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती रहने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती रहने के बावजूद मरीज को उपचारीय लाभ नहीं मिल रहा होता है। सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश एक सरल व सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इस विसंगति को दूर करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अस्पताल का आईसीयू मरीज की अनिश्चितकालीन देखभाल के लिए नहीं होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष अदालत ने समस्या के यथाशीघ्र समाधान की जरूरत पर बल दिया है। अदालत ने डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को संरक्षित करते हुए चिकित्सा संस्थानों व अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इस दिशा में व्यवस्थागत मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिसमें नर्स व मरीज के अनुपात, विशेषज्ञ पर्यवेक्षण, मानक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कराना एक सराहनीय पहल कही जाएगी। निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में भारी असमानता है, ये न्यूनतम मानदंड अधिक न्यायसंगत देखभाल के लिए आधार बन सकते हैं। सही मायनों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही निर्देश नीति के क्रियान्वयन हेतु तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन विगत के अनुभव बताते हैं कि एक अच्छे इरादे वाली कार्ययोजना तब अपने लक्ष्य पाने में विफल हो जाती हैं जब उसका क्रियान्वयन आधे-अधूरे ढंग से किया जाता रहा है। निश्चित रूप से निगरानी ढांचे और समन्वित राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई पर अदालत की पहल सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी अनुपालन की सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्त पोषण और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करेगी। साथ ही दक्षता के अलावा, मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गहन चिकित्सा कक्ष में लंबे समय तक भर्ती रहना मरीजों और उनके परिवारों के लिए बेहद कष्टदायक होता है। स्थिर मरीजों को कम स्तर पर देखभाल की जरूरत वाले वार्डों में स्थानांतरित किए जाने से न केवल अनावश्यक चिकित्सा खर्च बचता है। बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण का भी परिचायक है। निश्चित रूप से आईसीयू के लिए एकसमान मानदंड लागू करने का प्रयास भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।

घर-बाहर के दबाव में तनाव झेलती महिलाएं

> शोध के मुताबिक़, 72.2 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं उच्च तनाव में हैं, जो पुरुषों (53.64 प्रतिशत) से काफी अधिक है। 90 प्रतिशत महिलाएं यद्यपि मानती हैं कि स्वास्थ्य मुद्दे उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, तथापि भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण वे मदद मांगने से झिझकती हैं।

'मल्टीटॉस्किंग' एक नैसर्गिक गुण है, महिलाएं जिसमें विशेष रूप से माहिर मानी गई हैं। यूं भी अधिकतर भारतीय परिवारों में घरेलू कार्य स्त्रियों के ही हवाले रहते हैं, भले ही वह अतिरिक्त भार उठाने में सक्षम हो अथवा न। परंपरागत समाज के लिए यह आम बात हो सकती है किंतु परिवर्तित परिदृश्य में दोहरे दायित्व का निर्वहन कहीं न कहीं नारी-स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। हेल्थ स्टार्टअप त्राया द्वारा भारत के 15 राज्यों की 5,35,373 महिलाओं पर किया नवीनतम सर्वेक्षण देश में लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं के प्रतिदिन क्रॉनिक स्ट्रेस झेलने का ख़ुलासा करता है। पश्चिम बंगाल में 52.2 प्रतिशत महिलाएं तनाव की शिकार हैं, तमिलनाडु एवं दिल्ली में यह आंकड़ा क्रमशः 50.5 तथा 47.8 प्रतिशत है। सर्वाधिक चिंताजनक है, तनाव की कोई आकस्मिक घटना न होकर निरंतर चलने वाली समस्या बनना, जो कि नींद से लेकर महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य तक को चपेट में ले रही है।

सर्वे के निष्कर्ष बताते हैं कि कार्य तथा व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन, कार्यस्थल पर होने वाला भेदभाव, आर्थिक दबाव तथा सामाजिक अपेक्षाओं के फलस्वरूप उपजते तनाव से महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताएं बहुतेरे प्रभावित हो रही हैं। लगभग 5 में से 2 महिलाएं पर्याप्त निद्रा नहीं ले पा रहीं, वहीं हर 2 में से 1 महिला पेट तथा पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, असल में ये सभी दिक्कतें अलग-अलग न होकर परस्पर जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर यह उसी तनाव के परिणाम हैं, जिसे महिलाएं नित्यप्रति ढो रही हैं।

विशेषज्ञों की मानें तो, पारिवारिक-सामाजिक भूमिका के तहत महिलाओं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने वाली पारंपरिक

सोच तथा आधुनिक जीवनशैली के आपसी द्वंद्व ने समस्या और गहरा दी है। शोध के मुताबिक़, 72.2 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं उच्च तनाव में हैं, जो पुरुषों (53.64 प्रतिशत) से काफी अधिक है। 90 प्रतिशत महिलाएं यद्यपि मानती हैं कि स्वास्थ्य मुद्दे उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, तथापि भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण वे मदद मांगने से झिझकती हैं। इसका एक बड़ा कारण आज भी व्यापक स्तर पर व्याप्त लिंगभेद है।

सर्वे यह भी बताता है कि महिलाओं से लगातार ज़्यादा काम की उम्मीद पालने वाली संकीर्ण सोच में यह कम ही पूछा जाता है कि क्या उनके पास इसे निभाने के लिए ज़रूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बची भी है या नहीं? घर-कार्यस्थल में सामंजस्य बिठाने का प्रयास एवं प्रत्येक कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन की चाह तनाव के रूप में उभरकर उदासी, अवसाद, चिड़चिड़ेपन आदि अनेकानेक व्याधियों की उत्पत्ति का निमित्त बन रही है।

दुर्भाग्य से आज भी भारतीय समाज में मानसिक रोगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता। महिलाओं के संदर्भ में तो स्थिति विशेषकर निराशाजनक है। उनके स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक दायित्व अथवा सामाजिक जागरूकता के बारे तथ्य खंगालें तो सर्वे के मुताबिक़, अधिकांश मामलों में महिलाओं की भावनाओं एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, जिस कारण तनाव, चिंता गहरे अवसाद में परिणत होने लगते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी जटिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, साक्षरता का अभाव, निर्धनता तथा अंधविश्वासी प्रवृत्ति के चलते मानसिक रोगों को भूत-प्रेत की छाया अथवा जादू–टोने का प्रभाव मान लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरी मदद लेने की बजाय ओझा, तांत्रिक या झाड़-फूंक करने वालों को तरजीह दी जाती है, जो महिलाओं की हालत को और बिगाड़ देते हैं। कई मामलों में मौत तक हो जाती है। अपनी सेहत की अनदेखी करने में महिलाएं भी कम दोषी नहीं। आमतौर पर स्त्रीवर्ग अपना ध्यान रखने अथवा क्षमता के अनुरूप कार्य करने की बजाय दूसरों की ज़रूरतों को अधिक अधिमान देता है। सबका ख़्याल रखना निस्संदेह, एक सराहनीय गुण है, किंतु कर्तव्य-पालन के अतिरेक में यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि 'सबका' शब्द में महिलाएं ख़ुद भी शामिल हैं। तनाव ढोती महिलाओं की चुप्पी कालांतर में स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इससे पूर्व कि तनाव जीवन को अस्त-व्यस्त कर डाले, काउंसलिंग करना अनिवार्य हो जाता है।

असल में, नर-नारी, परिवार तथा समाज रूपी गाड़ी चलाने वाले दो पहिए हैं। किसी भी पहिए पर क्षमता से अधिक बोझ लादना उसे क्षतिग्रस्त बना छोड़ेगा। देश की आधी आबादी का स्थाई तौर पर तनाव से जूझना मात्र स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा न होकर समग्र रूप में एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है। मानवीय आधार पर समझना होगा कि महिलाओं की भावनात्मक ज़रूरतें भी पुरुषों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अनदेखा करना सरासर अन्याय है।

डॉक्टरों के कथनानुसार, दीर्घकालीन तनाव के प्रति बरती गई कोताही भविष्य में असाध्य रोग बन सकती है। भीतर ही भीतर घुटने की अपेक्षा क्यों न परिजनों को शिष्टतापूर्वक अपनी मनोस्थिति से अवगत करवाया जाए ताकि समय रहते समुचित समाधान मिल सके? इसके लिए समाज, परिवार तथा सरकार को मिलकर एक ऐसा माहौल सृजित करना होगा, जहां महिलाएं निःसंकोच अपनी समस्याएं साझा कर सकें। मिल-बांटकर काम करने से जहां कार्यभार घटेगा, वहीं रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी; तनावरहित नारी अधिक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा स्वस्थ जीवन जी पाएगी।

प्रेरणा

लगातार सुधार की शक्तिः धैर्य, अभ्यास और आत्मविकास की यात्रा

एक युवा संगीतकार के मन में गहरी बेचैनी थी। उसे लगता था कि वह चाहे जितना प्रयास कर ले, वह कभी भी महान कलाकारों की श्रेणी में नहीं पहुँच पाएगा। उसके भीतर यह धारणा बन चुकी थी कि कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और वही असाधारण ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं, जबकि बाकी लोग केवल औसत बने रहते हैं। इसी निराशा के साथ वह महान जर्मन संगीतकार Ludwig van Beethoven के पास पहुँचा और अपनी व्यथा व्यक्त की। उसने कहा कि उसमें वह विशेष गुण नहीं है, जो किसी को महान बनाता है। बीथोवेन ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने न तो उसकी बात को तुरंत खारिज किया और न ही उसे झूठी दिलासा दी। इसके बजाय उन्होंने उसे अपने अभ्यास-कक्ष में आने के लिए कहा। वहाँ पहुँचकर युवक ने सोचा कि शायद उसे कोई नया रहस्य या तकनीक सिखाई जाएगी, जो उसे अचानक महान बना देगी। लेकिन जो हुआ, वह उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग था। बीथोवेन ने पियानो पर एक साधारण-सी धुन बजानी शुरू की। उन्होंने उसे बार-बार दोहराया। हर बार वह धुन थोड़ी-सी बदलती, कहीं स्वर में हल्का-सा अंतर आता, कहीं लय में मामूली परिवर्तन होता। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। युवक पहले तो ध्यान से देखता रहा, लेकिन धीरे-धीरे उसे यह सब एकरस और उबाऊ लगने लगा। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि इतना महान संगीतकार एक ही छोटी-सी धुन पर इतना समय क्यों खर्च कर रहा है। आखिरकार उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उसने पूछा कि जब वह पहले से ही इतने महान हैं, तो फिर इस तरह एक ही हिस्से को बार-बार सुधारने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बीथोवेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि अक्सर महानता वहीं छिपी होती है, जहाँ लोग अधीर होकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। उन्होंने समझाया कि कोई भी उत्कृष्ट रचना अचानक नहीं बनती, बल्कि वह छोटे-छोटे सुधारों की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है। उन्होंने युवक से कहा कि प्रतिभा केवल शुरुआत कराती है, लेकिन उत्कृष्टता तक पहुँचने के लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग केवल नए-नए काम करने में लगे रहते हैं, वे अक्सर गहराई हासिल नहीं कर पाते। इसके विपरीत, जो लोग एक ही कार्य को बार-बार सुधारते हैं, वे उसमें ऐसी बारीकियाँ खोज लेते हैं, जो दूसरों को दिखाई नहीं देतीं।

यह बात युवक के मन में गहराई तक उतर गई। उसने अपने अभ्यास के तरीके को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। अब वह जल्दी-जल्दी नई धुनें सीखने के बजाय एक ही रचना पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह हर दिन अपने काम को थोड़ा-सा बेहतर बनाने की कोशिश करता। वह अपनी गलतियों को पहचानता, उन्हें सुधारता और फिर उसी प्रक्रिया को दोहराता। शुरुआत में उसे यह तरीका धीमा और कठिन लगा, लेकिन धीरे-धीरे उसे इसके परिणाम दिखाई देने लगे।

उसके संगीत में पहले से अधिक स्पष्टता आने लगी। उसकी धुनों में भावनाओं की गहराई बढ़ गई। अब वह केवल नोट्स नहीं बजा रहा था, बल्कि अपने संगीत के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। यह परिवर्तन धीरे-धीरे हुआ, लेकिन यह स्थायी और प्रभावशाली था। यह कहानी केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आज के समय में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कम समय में अधिक सफलता मिल जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास, हर जगह यही सिद्धांत काम करता है। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस समय का सही उपयोग करना है। जब हम किसी काम को बार-बार करते हैं और हर बार उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, तब हम वास्तव में अपने कौशल को निखार रहे होते हैं। यह प्रक्रिया कभी-कभी नीरस लग सकती है, लेकिन यही नीरसता हमें मजबूत बनाती है। जो लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वही अंततः दूसरों से अलग पहचान बना पाते हैं।

अनुशासन इस यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक लगातार प्रयास नहीं कर सकता। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जब हम रोजाना अपने काम पर ध्यान देते हैं और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तब धीरे-धीरे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है।

इसके अलावा, छोटे-छोटे सुधारों का महत्व भी बहुत बड़ा है। अक्सर लोग बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे-छोटे सुधार ही बड़े परिणाम लाते हैं। जब हम हर दिन थोड़ा-सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ यह छोटा-सा सुधार एक बड़ी उपलब्धि में बदल जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम या तो निराश हो जाते हैं या फिर अहंकार में आ जाते हैं। दोनों ही स्थितियाँ हमारे विकास के लिए बाधा बनती हैं। इसके विपरीत, जब हम अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, तो हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद, वह युवक जो पहले खुद को असमर्थ मानता था, अब आत्मविश्वास से भर गया था। उसकी कला में वह गहराई आ चुकी थी, जिसकी उसे तलाश थी। यह परिवर्तन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, बल्कि निरंतर अभ्यास, धैर्य और छोटे-छोटे सुधारों का फल था। यह हमें सिखाता है कि महानता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, जो समय और प्रयास से विकसित होती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर दिन का छोटा-सा प्रयास भी महत्वपूर्ण है, तब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यही सोच हमें जीवन में आगे ले जाती है और हमें वह बनने में मदद करती है, जो हम बनना चाहते हैं।N अंततः, सफलता का असली रहस्य इसी में छिपा है कि हम अपने काम के प्रति समर्पित रहें, धैर्य बनाए रखें और लगातार सुधार करते रहें। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने लगते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

4 मई के बाद बदल जाएगी देश की राजनीति

देश के चार राज्यों- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ चुके है। इस बार का विधानसभा चुनाव , इस मायने में बहुत खास है कि इसमें देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों- कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके जैसे ताकतवर क्षेत्रीय दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। सबसे बड़ा सवाल तो लेफ्ट फ्रंट के दलों के सामने खड़ा हो गया है क्योंकि केरल की सत्ता हाथ से जाते ही उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट पार्टियां पहले ही साफ हो चुकी है।जाहिर है कि इन पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजें सिर्फ इन राज्यों के मुख्यमंत्री ही तय नहीं करेंगे बल्कि दोनों गठबंधन- एनडीए एवं इंडिया को भी प्रभावित करेंगे। यह भी एक तथ्य है कि चाहे, चुनावी नतीजे जो भी आए लेकिन इसके बाद देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में तेजी से बड़े बदलाव दिखाई देने लगेंगे।

बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कई महीने पहले ही बदलाव की शुरुआत कर दी थी लेकिन वह बदलाव अभी संगठन के ढांचे और सरकार तक नहीं पहुंच पाया है। बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद नितिन नवीन की नई टीम के गठन के लिए उच्चस्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा। बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि वो बुजुर्ग हो चुके नेताओं को संगठन से बाहर रहने के लिए कैसे मना पाते हैं क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष चुनने के बाद पार्टी उनकी टीम को भी युवा नेताओं से ही भरना चाहती है। पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी को पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च ईकाई संसदीय बोर्ड, उम्मीदवारों का चयन करने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों और मोर्चों का पुनर्गठन करना है। पार्टी में नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया सहित विभिन्न विभागों की टीम के साथ ही राष्ट्रीय मोर्चों का भी पुनर्गठन करना है। इसके बाद बदलाव की यही प्रक्रिया सरकार और राज्यों में भी की जानी है। नई टीम में एक तरफ जहां युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन बनाना होगा वहीं महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जगह देनी होगी। बताया जा रहा है कि 4 मई को चुनावी नतीजे आने के 10-15 दिनों के अंदर नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो सकता है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का पूरा स्वरूप ही बदला-बदला नजर आएगा।

कांग्रेस में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की शुरुआत आने वाले दिनों में होने जा रही है। मोदी-शाह की जोड़ी ने 46 वर्ष के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राहुल और सोनिया गांधी के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझे हुए परिपक्व नेता तो हैं लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भी एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ युवा नेताओं की टीम तो खड़ी करनी ही पड़ेगी। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। ऐसे में जाहिर से बात है कि कांग्रेस को राहुल और प्रियंका गांधी से इतर जाकर अन्य युवा नेताओं की तरफ देखना पड़ेगा। इस रेस में फिलहाल सचिन पायलट सबसे आगे बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों के चहेते नेता सचिन पायलट को आने वाले दिनों में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अगर अशोक गहलोत ने पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के साथ मिलकर कोई और खेला नहीं कर दिया तो। ध्यान दीजिएगा कि, यह अकारण नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से गहलोत बार-बार पायलट की बगावत का किस्सा सुनाने में लगे हुए है। लेकिन अगर पायलट का नाम पीछे छूट भी गया तो भी राहुल गांधी को पार्टी के लिए नया और वो भी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ढूंढना ही पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की गुटबाजी पर लगाम कसने के लिए खड़गे को मुख्यमंत्री बनाकर बेंगलुरू भेजा जा सकता है और उनकी जगह पर दिल्ली में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर खड़गे कर्नाटक जाएंगे तो फिर पार्टी को राज्यसभा में भी अपना नया नेता चुनना पड़ेगा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी किसी युवा नेता को ही बनाना पड़ेगा और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में भी नए चेहरों की संख्या बढ़ जाएगी। यह तय मान कर चलिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में मई के महीने में ही बदलाव होना तय है। हालांकि कांग्रेस में बदलाव की यह रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है।

अभियान

हिमालय की गोद में छिपा रहस्यः भीम की पकड़ से प्रकट हुआ केदारनाथ का दिव्य शिवलिंग

हिमालय की शांत, भव्य और रहस्यमयी वादियों के बीच स्थित Kedarnath Temple सदियों से श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। ऊँचे बर्फीले पहाड़, पतली हवाएँ और कठिन मार्ग इस धाम को जितना भौतिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, उतना ही यह आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव भी प्रदान करता है। हर वर्ष जब इसके कपाट खुलते हैं, तो देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवित धड़कन है, जहाँ हर पत्थर में इतिहास और हर हवा के झोंके में दिव्यता का अनुभव होता है।

केदारनाथ धाम विशेष रूप से इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यहाँ स्थापित शिवलिंग का स्वरूप अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। जहाँ अधिकांश शिवलिंग गोलाकार या लिंगाकार होते हैं, वहीं केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणीय और उभरा हुआ है, जो देखने में बैल की पीठ के समान प्रतीत होता है। यह स्वरूप न केवल अद्भुत है, बल्कि इसके पीछे एक गहन पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जो सीधे-सीधे Mahabharata काल से संबंध रखती है। मान्यता के अनुसार, महाभारत युद्ध के पश्चात Pandavas गहरे पश्चाताप से भर गए थे। अपने ही संबंधियों के विनाश का बोझ उनके मन पर इतना भारी था कि उन्हें शांति का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान Lord Shiva की शरण में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। इसी उद्देश्य से वे हिमालय की कठिन और लंबी यात्रा पर निकल पड़े, साथ में Draupadi भी थीं।

लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। वे पांडवों के कर्मों की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं को नंदी अर्थात बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया और हिमालय के इस क्षेत्र में छिप गए। पांडव उन्हें ढूँढ़ते-ढूँढ़ते केदार क्षेत्र तक पहुँच गए। यहाँ उन्हें एक असामान्य बैल दिखाई दिया, जिसकी गतिविधियाँ सामान्य नहीं थीं। भीम, जो अपनी अपार शक्ति और तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण पशु नहीं हो सकता।

भीम ने उस बैल को पकड़ने के लिए अपनी विशाल भुजाएँ फैलाईं और उसे जकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, बैल अचानक भूमि में समाने लगा। यह दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। भीम ने तुरंत उसकी पूँछ को पकड़ लिया, ताकि वह पूरी तरह से अदृश्य न हो जाए। लेकिन भगवान शिव की लीला निराली थी। बैल का शरीर धीरे-धीरे धरती में विलीन होता गया, और अंततः उसका पीठ वाला भाग केदारनाथ में ही प्रकट रह गया। यही भाग आज शिवलिंग के रूप में पूजित है, जो बैल की पीठ के समान दिखाई देता है।

यह घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भी भरी हुई है। बैल, जो नंदी के रूप में शिव का वाहन है, समर्पण, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। केदारनाथ का यह शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे पश्चाताप और भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसे मार्ग अवश्य मिलता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो।

इस घटना के बाद भगवान शिव के शरीर के अन्य अंग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज 'पंचकेदार' के नाम से जाना जाता है। Tungnath Temple में उनकी भुजाएँ प्रकट हुईं, Rudranath Temple में उनका मुख, Madhyamaheshwar Temple में नाभि और Kalpeshwar Temple में उनकी जटाएँ प्रकट हुईं। इन पाँचों धामों की यात्रा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इसे पूर्ण करने वाले श्रद्धालु को विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है।

केदारनाथ धाम की एक और विशेषता इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं। यह स्थान वर्ष के लगभग छह महीने तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की ठंडी हवाएँ, कठिन चढ़ाई और सीमित संसाधन इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन यही कठिनाइयाँ इस यात्रा को और अधिक पवित्र और अर्थपूर्ण बना देती हैं। श्रद्धालु जब इन कठिनाइयों को पार करके मंदिर तक पहुँचते हैं, तो उनके भीतर एक अद्भुत संतोष और शांति का अनुभव होता है।

साल 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। चारों ओर तबाही का मंजर था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मंदिर को कोई विशेष क्षति नहीं पहुँची। यह घटना लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर गई। इसे भगवान शिव की कृपा और इस धाम की दिव्यता का प्रमाण माना गया। इसके बाद से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और भी वृद्धि हुई है।

मंदिर के आसपास कई ऐसी प्राकृतिक आकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें श्रद्धालु माता पार्वती और पांडवों की छवियों के रूप में पहचानते हैं। ये आकृतियाँ किसी मानव द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई मानी जाती हैं। यह भी इस स्थान के रहस्य और आकर्षण को और बढ़ाता है।

यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और शांत होता है कि व्यक्ति अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करता है। हिमालय की ऊँचाइयों पर स्थित यह धाम केवल शरीर की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। यहाँ पहुँचकर व्यक्ति अपने जीवन की भागदौड़ और तनाव को भूल जाता है और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है।

केदारनाथ का शिवलिंग, जो बैल की पीठ के समान दिखाई देता है, केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक गहन दर्शन को भी दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और सच्ची भक्ति का क्या महत्व है। यह हमें यह भी बताता है कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होती।

आज के आधुनिक युग में, जब लोग तेजी से सफलता पाने की होड़ में लगे हुए हैं, केदारनाथ की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची उपलब्धि धैर्य और समर्पण से ही प्राप्त होती है। यह स्थान हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है।

अंततः, केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जो हर व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यहाँ की यात्रा केवल पैरों से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से की जाती है। जब कोई श्रद्धालु इस धाम से लौटता है, तो वह केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा, नई सोच और एक गहरी शांति अपने साथ लेकर जाता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

चोरी हुए मोबाइल रिकवर करने में गुजरात पुलिस देशभर में तीसरे स्थान पर

गुजरात पुलिस ने 46.71 प्रतिशत रिकवरी रेट के साथ पिछले एक वर्ष में 53,564 हैंडसेट सफलतापूर्वक मूल मालिकों को सौंपे

मोबाइल रिकवरी में श्रेष्ठ कार्य के लिए अहमदाबाद शहर, डांग तथा भावनगर जिलों के नोडल अधिकारियों को राज्य पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव द्वारा सम्मानित किया गया

गांधीनगर : राज्य में चोरी हुए मोबाइल खोज निकालने में गुजरात पुलिस समग्र देश के बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊँचा रिकवरी रेट हासिल कर गुजरात पुलिस ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गुजरात पुलिस ने 46.71 प्रतिशत के रिकवरी रेट के साथ 53,564 हैंडसेट सफलतापूर्वक मूल मालिक को सौंपे। गुजरात में मोबाइल रिकवरी में श्रेष्ठ कार्य के लिए अहमदाबाद शहर, डांग तथा भावनगर जिलों के नोडल अधिकारियों को राज्य पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव द्वारा सम्मानित किया गया।

टेलीकॉम विभाग (डीओटी) तथा गुजरात पुलिस के संयुक्त प्रयासों से गुजरात राज्य ने मोबाइल हैंडसेट रिकवरी में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के 'संचार साथी' पोर्टल तथा सीईआईआर मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग द्वारा गुजरात ने देश के बड़े राज्यों की सूची में रिकवरी के प्रतिशत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

मोबाइल रिकवरी क्षेत्र में गुजरात ने राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। समग्र भारत में अब तक 50,48,516 मोबाइल ब्लॉक किए गए हैं; जिसके समक्ष गुजरात में कुल 1,83,985 हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल रिकवरी की दर 32.6 प्रतिशत है, जबकि गुजरात पुलिस ने 46.71 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ 53,564 हैंडसेट सफलतापूर्वक रिकवर किए हैं। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण बड़े राज्यों की सूची में गुजरात समग्र देश में तीसरे स्थान पर रहा है।

वर्ष 2025-26 के डेटा के अनुसार सीईआईआर रैंकिंग में अहमदाबाद शहर, डांग तथा भावनगर जिलों ने श्रेष्ठ कामकाज किया है। जिलेवार कार्य विवरण देखें, तो अहमदाबाद शहर ने सर्वाधिक 25,500 ब्लॉक रिक्वेस्ट के समक्ष 4,935 हैंडसेट रिकवर कर 56.70 के फाइनल स्कोर के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। डांग जिला 328 ब्लॉक रिक्वेस्ट तथा 77.33 प्रतिशत के ऊँचे एकुरेसी स्कोर के साथ 54.89 पॉइंट्स प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा है।

इसके अतिरिक्त; भावनगर जिले ने 634 ब्लॉक रिक्वेस्ट के समक्ष 273 मोबाइल रिकवर कर 53.44 के स्कोर के साथ राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। यह डेटा दर्शाता है कि ब्लॉक करने के बाद ट्रेस हुए 1,14,670 हैंडसेट को खोजने में गुजरात के विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अहमदाबाद शहर 25,500 ब्लॉक रिक्वेस्ट के साथ वॉल्यूम स्कोर में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहा है।

गुजरात एलएसए द्वारा लागू किए गए 'सीईआईआर रैंकिंग फ्रेमवर्क' अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अहमदाबाद शहर, डांग तथा भावनगर जिलों में श्रेष्ठ कार्य हुआ है। राज्य पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव ने इन जिलों के नोडल अधिकारियों को उनके अनन्य कार्य के लिए शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना, चोरी हुए हैंडसेट का दुरुपयोग रोकना तथा टेलीकॉम संबंधी धोखाधड़ी पर नियंत्रण हासिल करना है।

'वन क्लिक' से उद्योगों को संजीवनी: 1349 करोड़ की सब्सिडी से सूरत में निवेश और विकास को नई रफ्तार

सूरत। 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' से ठीक पहले गुजरात सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 'वन क्लिक' प्रणाली के जरिए 11 हजार से अधिक उद्योगपतियों को 1349 करोड़ की सब्सिडी सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे राज्य के औद्योगिक माहौल में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पहल को सरकार की पारदर्शिता और त्वरित निर्णय क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है, जिसने उद्योगों और प्रशासन के बीच विश्वास को और मजबूत किया है।

गृह राज्य मंत्री Harsh Sanghavi ने सूरत दौरे के दौरान कुछ ही सेकंड में यह राशि डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इस 'वन क्लिक' ट्रांसफर ने यह दिखाया कि तकनीक के सही उपयोग से सरकारी योजनाओं का लाभ कितनी तेजी और प्रभावशीलता से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। उद्योग जगत के लिए यह न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि यह संदेश भी है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है।

सब्सिडी वितरण में विभिन्न सेक्टरों को शामिल किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचे। MSME क्षेत्र की 7,495 इकाइयों को 299.75 करोड़ की सहायता दी गई, जो छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। टेक्सटाइल सेक्टर, जो सूरत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, के 3,423 लाभार्थियों को 538.76 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा बड़े उद्योगों के 111 लाभार्थियों को 510.99 करोड़ की सहायता दी गई, जिससे बड़े निवेश और उत्पादन क्षमता को भी बल मिला है।

इस अवसर पर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री हर्ष सांघवी ने उद्योगपतियों से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल कमियों को उजागर करने से विकास नहीं होता, बल्कि समाधान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग ही राज्य में अधिक निवेश आकर्षित करने की कुंजी है। उनका यह बयान इस बात को रेखांकित करता है कि सरकार उद्योगों को साझेदार के रूप में देख रही है, न कि केवल लाभार्थी के रूप में। इसी बीच, सूरत में आयोजित होने वाली 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के दौरान एक और बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। 'डीप सी डिस्चार्ज प्रोजेक्ट' के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता (MOU) प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 5,000 से 6,000 करोड़ के बीच बताई जा रही है। इस परियोजना के तहत 7 से 8 ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध किया गया पानी 8 से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में छोड़ा जाएगा। यह प्रोजेक्ट जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

इस परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें 80 प्रतिशत फंड सरकार और 20 प्रतिशत उद्योगों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे यह एक संयुक्त प्रयास का उदाहरण बनता है। इसके साथ ही उद्योगों में 'टर्शियरी ट्रीटेड वॉटर' के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पेयजल की बचत होगी और घरेलू तथा कृषि उपयोग के लिए अधिक पानी उपलब्ध हो सकेगा। यह पहल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ संसाधनों के सतत उपयोग को भी सुनिश्चित करेगी।

उद्योग संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। South Gujarat Chamber of Commerce and Industry के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र के उद्योगपतियों में जबरदस्त उत्साह है। उनके अनुसार, यह सम्मेलन उद्योगों और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा, जिससे नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता और गति आएगी।

अमृत भारत स्टेशनों से बदली रेलवे की सूरतः वडोदरा मंडल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, गति और सुरक्षा में बड़ा सुधार

वडोदरा। भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है, जहाँ योजनाबद्ध विकास, तकनीकी उन्नयन और यात्री सुविधाओं के विस्तार ने रेलवे की तस्वीर को ही बदल दिया है।

Indian Railways के अंतर्गत आने वाले इस मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक अनुरक्षण, संरचना सुदृढ़ीकरण और यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगति दर्ज की है, वह न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय मानी जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक Raju Bhadke के कुशल नेतृत्व में यह परिवर्तन संभव हुआ है, जिसने रेलवे को अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में ठोस आधार तैयार किया है।

इस व्यापक बदलाव का सबसे प्रमुख चेहरा बनी है Amrit Bharat Station Scheme, जिसके अंतर्गत वडोदरा मंडल के कई स्टेशनों का कायाकल्प किया गया। प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा 22 मई 2025 को देशभर के 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिनमें वडोदरा मंडल के उत्राण, कोसंबा, डेरोल, डाकोर और करमसद स्टेशन भी शामिल रहे। इन स्टेशनों पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, उन्नत टिकट काउंटर, स्वच्छ एवं मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके साथ ही प्रतापनगर और गोधरा स्टेशन भी इसी योजना के अंतर्गत तैयार हो चुके हैं, जो आने वाले समय में यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव देने के लिए तैयार हैं।

वडोदरा मंडल ने केवल स्टेशन सौंदर्यीकरण तक ही अपने प्रयास सीमित नहीं रखे, बल्कि सुरक्षा और ट्रैक गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करते हुए 5 रोड ओवर ब्रिज (ROB) और 3 रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया गया, जिससे रेल और सड़क यातायात दोनों में सुरक्षा और सुगमता बढ़ी है। ट्रैक कार्यों के अंतर्गत 169.189 यूनिट कम्प्लीट ट्रैक रिन्यूअल (CTR), 192.128 ट्रैक किलोमीटर थ्रू रेल रिन्यूअल (TRR) और 118.291 ट्रैक किलोमीटर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल (TSR) जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं, जो रेल संचालन की विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं।

संरचना सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में भी मंडल ने प्रभावशाली काम किया है। 15 पुलों का पुनर्वास, 5 पुलों की री-गर्डरिंग और 33 पुलों पर एप्रोच ट्रांजिशन कार्यों ने रेलवे नेटवर्क की मजबूती को और बढ़ाया है। इसके अलावा 906 स्टील चैनल स्लीपरों का नवीनीकरण किया गया, जिससे पुलों की स्थिरता और सुरक्षा में सुधार हुआ है। ये सभी कार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि रेलवे केवल तेज ही नहीं, बल्कि सुरक्षित भी रहे।

यार्ड और तकनीकी सुधारों में भी वडोदरा मंडल ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 9 यार्डों में 14 लेआउट का सुधार किया गया, 972 टर्नआउट का मानकीकरण किया गया और TWS तथा WCMSC जैसे आधुनिक तकनीकी सिस्टम को शामिल किया गया। 68 यार्डों में PRL लाइनों का उन्नयन और 2472 स्थानों पर फ्री जॉइंट्स का उन्मूलन किया गया, जिससे ट्रैक की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। इसका सीधा असर ऑस्सिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OMS) के आंकड़ों में भी दिखा, जहाँ 0.15g से अधिक मान में 93.25% की कमी दर्ज की गई—जो ट्रैक स्थिरता और ट्रेन संचालन की गुणवत्ता में सुधार का स्पष्ट संकेत है।

यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। डेरोल स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज (FOB) तैयार किया गया है, जबकि अन्य 8 स्टेशनों पर इसी प्रकार के FOB निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा मंडल ने 20 प्लेटफार्मों का विस्तार और उन्नयन किया है, 13 स्टेशनों पर कोचिंग ऑपरेशन पैनल (COP) की सुविधा शुरू की है और 3 नए 6 मीटर चौड़े FOB का निर्माण किया है। 9 स्टेशनों पर कवर शेड बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को मौसम की मार से राहत मिलती है।

सुगम और समावेशी यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 47 स्टेशनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है, जहाँ लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियाँ, रैंप और भूमिगत मार्ग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए 104 नए आवासों का निर्माण भी किया गया है, जो कार्यबल की दक्षता और संतुष्टि को बढ़ाने में सहायक होगा।

इन सभी प्रयासों का समग्र प्रभाव यह है कि वडोदरा मंडल अब एक आधुनिक, सुरक्षित और यात्री-हितैषी रेलवे नेटवर्क के रूप में उभर रहा है। यह न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि रेल संचालन की गति और विश्वसनीयता को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है।

पश्चिम रेलवे का यह मॉडल आने वाले समय में अन्य मंडलों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। जिस प्रकार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी नवाचार और यात्री सुविधाओं का संतुलित विकास यहाँ देखने को मिला है, वह भारतीय रेल के भविष्य की दिशा को स्पष्ट करता है। वडोदरा मंडल की यह प्रगति यह दर्शाती है कि यदि संकल्प और योजना स्पष्ट हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीन पर दिखता है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है।

सूरत SBI लूट कांडः अलार्म फेल, CCTV बेअसर-50 लाख की डकैती में सिस्टम पर उठे बड़े सवाल

सूरत। गुजरात के सूरत शहर में दिनदहाड़े हुई बैंक डकैती ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वराछा इलाके के लंबे हनुमान रोड स्थित State Bank of India (SBI) की शाखा में हुई इस वारदात में 5 से 6 हथियारबंद बदमाश करीब 50 लाख रुपये की नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है, जबकि जांच के लिए आठ टीमें गठित कर 200 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले जा चुके हैं।

मामले की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा बैंक के अलार्म सिस्टम को लेकर हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, लुटेरों ने अलार्म के तार नहीं काटे थे, बल्कि सिस्टम पहले से ही काम नहीं कर रहा था। घटना के दौरान बैंक मैनेजर सहित दो कर्मचारियों ने अलार्म बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वह सक्रिय नहीं हुआ। सुरक्षा का यह सबसे अहम साधन फेल होने से लुटेरों को बिना किसी बाधा के वारदात को अंजाम देने का मौका मिल गया।

बताया जा रहा है कि यदि अलार्म सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होता, तो तत्काल पुलिस को सूचना मिल सकती थी और बदमाशों को मौके के आसपास ही घेरा जा सकता था। लेकिन सिस्टम की विफलता ने न केवल वारदात को आसान बना दिया, बल्कि पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया की संभावना भी खत्म कर दी। इस खुलासे के बाद बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है।

घटना मंगलवार को उस समय हुई, जब बैंक में सामान्य कामकाज चल रहा था। अचानक 5-6 हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे और कर्मचारियों को धमकाकर कैश काउंटर और तिजोरी से लाखों रुपये लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश बेहद संगठित और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पहले से पूरी योजना बनाई थी। वारदात के दौरान उन्होंने तिजोरी की चाबी मांगी और करीब 40 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये छोड़कर भाग जाना भी कई सवाल खड़े करता है—क्या यह जल्दबाजी थी या किसी रणनीति का हिस्सा?

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस महकमे में भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बैंक का निरीक्षण किया। इसके बाद जांच के लिए आठ विशेष टीमें बनाई गईं, जिन्होंने सूरत के वेलंजा से लेकर पालसाना और आसपास के कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। 200 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है।

पुलिस को आशंका है कि इस वारदात के पीछे कोई संगठित गिरोह हो सकता है, जो संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बिहार से जुड़ा हुआ है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं, जिसमें बैंक के अंदरूनी पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

इस लूट कांड ने एक बार फिर बैंक सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल यह उठ रहा है कि इतने संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा उपकरण जैसे अलार्म सिस्टम का काम न करना कैसे संभव है? क्या नियमित जांच और मेंटेनेंस नहीं किया गया था? यदि ऐसा है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर चूक मानी जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक जैसे संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था बहुस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें अलार्म, CCTV, गार्ड और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया शामिल होती है। इनमें से किसी एक कड़ी के कमजोर पड़ने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला।

फिलहाल पुलिस जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस सुराग सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल तकनीकी संसाधनों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही तरीके से काम करना और नियमित निगरानी भी उतनी ही जरूरी है।

सूरत की इस वारदात ने न केवल स्थानीय प्रशासन, बल्कि देशभर के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक चेतावनी का काम किया है। अब देखना होगा कि इस घटना से क्या सबक लिया जाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

भावनगर मंडल में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का शुभारंभ-आपातकालीन परिस्थितियों में महिलाओं को मिलेगी त्वरित सुविधा

कर्मचारी हित निधि के सौजन्य से पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2026 (गुरूवार) को एक सराहनीय पहल के अंतर्गत बाल मंदिर एवं किड्स हट स्कूल के प्रांगण में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने विधिवत रिबन काटकर मशीन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं गरिमा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि इस मशीन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में शिक्षिकाओं एवं अन्य महिला कर्मचारियों को त्वरित एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उद्घाटन समारोह के दौरान संगठन की उपाध्यक्षा, सचिव एवं अन्य सदस्यगण के साथ-साथ विद्यालय की शिक्षिकाएँ भी उपस्थित रहीं। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उपयोगी कदम बताया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से विश्व गुजराती समाज के 'विश्वमेळो' के नवसंचार विशेषांक तथा नई अद्यतन वेबसाइट की लॉन्चिंग

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती संस्कृति, गुजराती भाषा तथा विश्वभर में बसने वाले गुजरातियों की विभिन्न उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने वाली तथा नित-नवीन पठन सामग्री से भरपूर 'विश्वमेळो' (विश्वमेला) नवसंचार विशेषांक एवं नई अद्यतन वेबसाइट की गुरुवार को गांधीनगर में लॉन्चिंग की।

विश्व गुजराती समाज द्वारा प्रकाशित 'विश्वमेळो' नवसंचार विशेषांक में गुजराती भाषा-संस्कृति के संवर्धन, वैश्विक स्तर पर गुजरातियों की उपलब्धियों तथा समाज के विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट किया गया है।

नवसंचार को प्राप्त इस सामयिक में अब पाठकों को नूतन विचार, नई पहलें, नए विभाग तथा नई-नई जानकारियाँ जानने को मिलेंगे और गुजराती संगठनों तथा विभिन्न समाजों के समाचार जानने को मिलेंगे। इतना ही नहीं; 'विश्वमेळो' के अंकों में युवा वर्ग, महिला वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए उपयोगी सामग्री का समावेश किया जाएगा।

विश्व गुजराती समाज की नई अद्यतन वेबसाइट विश्वभर के गुजरातियों को एक मंच प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से समाज के सदस्यों के बीच और अच्छा जुड़ाव एवं जानकारी का प्रवाह आसान बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर गुजराती संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार के लिए विश्व गुजराती समाज के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने ऐसी पहलों को गुजरात की वैश्विक पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली बताया।

विश्व गुजराती समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री भावेश लाखाणी ने गुजराती समाज को संगठित एवं सशक्त बनाने के उनके विजन के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर सर्वश्री महेंद्रभाई शाह, सुधीर रावल, योगेशभाई लाखाणी, नयनभाई परीख, मनीषभाई शर्मा, बिपिनभाई सोनी आदि उपस्थित रहे।

सूरत में शू फैब्रिक इंडस्ट्री का उभार: MSME की ताकत से बन रही नई औद्योगिक पहचान

सूरत। देश की टेक्सटाइल राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना चुका सूरत अब एक नए औद्योगिक आयाम की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। पारंपरिक कपड़ा उद्योग के साथ-साथ शहर में शू फैब्रिक—यानी जूतों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े—का सेक्टर तेजी से उभर रहा है। जहां सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30–40 वर्षों का मजबूत आधार हासिल है, वहीं शू फैब्रिक का उत्पादन पिछले एक दशक में शुरू होकर अब एक महत्वपूर्ण और संभावनाओं से भरे क्षेत्र के रूप में सामने आ रहा है। खासकर पिछले 5–6 वर्षों में इस उद्योग ने जिस गति से विकास किया है, उसने इसे MSME सेक्टर की सफलता का नया उदाहरण बना दिया है।

टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, इस उभार के पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे अहम है स्पोर्ट्स और कैजुअल फुटवियर की बढ़ती मांग, जिसने शू फैब्रिक की खपत को लगातार बढ़ाया है। इसके साथ ही चीन से आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीति ने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। सूरत पहले से ही पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे मैन-मेड फाइबर (MMF) का मजबूत केंद्र रहा है, जो शू फैब्रिक निर्माण का आधार बनते हैं। यही वजह है कि इस नए सेगमेंट को यहां तेजी से विकसित होने का अनुकूल वातावरण मिला। वर्तमान में सूरत में कुल टेक्सटाइल उत्पादन लगभग 6.5 करोड़ मीटर प्रतिदिन आंका जाता है। हालांकि इसमें शू फैब्रिक की हिस्सेदारी अभी सीमित है, लेकिन इसकी वृद्धि दर बेहद तेज है। उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, शहर में प्रतिदिन करीब 5 से 15 लाख मीटर शू फैब्रिक का उत्पादन हो रहा है। इसमें मेश, निटेड, PU कोटेड और नॉनवोवन जैसी विविध श्रेणियां शामिल हैं, जो अलग-अलग प्रकार के फुटवियर के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इस उद्योग की सबसे खास बात यह है कि इसका नेतृत्व बड़े कॉरपोरेट्स नहीं, बल्कि MSME इकाइयां कर रही हैं। ये छोटी और मध्यम इकाइयां अपनी लचीलापन, नवाचार क्षमता और तेज उत्पादन के कारण बाजार में तेजी से जगह बना रही हैं। बड़ी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स भी सीधे उत्पादन करने के बजाय इन्हीं स्थानीय निर्माताओं से फैब्रिक सोर्स कर रही हैं, जिससे सूरत के MSME सेक्टर को वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। सूरत में इस क्षेत्र में सक्रिय कई प्रमुख इकाइयां अपने-अपने सेगमेंट में विशेष पहचान बना रही हैं। इनमें PU लेदर आधारित शू फैब्रिक बनाने वाली ओम टेक्सटाइल, महिला फुटवियर फैब्रिक के लिए जानी जाने वाली प्रवीन ओवरसीज, नॉनवोवन फैब्रिक में अग्रणी रेडियंस स्पूनबांड प्राइवेट लिमिटेड, निटेड फैब्रिक के लिए निमबर्क फैब्रिक्स, स्पोर्ट्स फैब्रिक में विशेषज्ञ श्रीयान टेक्सफैब, मधुसूदन ग्रुप की सुदामो इम्पेक्स और स्टार नीट्स जैसी इकाइयां शामिल हैं।

66वें 'गुजरात गौरव दिवस' के अवसर पर मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश

आज पूरी दुनिया गुजरात के विकास मॉडल से प्रभावित होकर गुजरात की ओर आकर्षित हुई है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की ओर से देश और दुनिया में बसे सभी प्यारे गुजराती भाई-बहनों को 1 मई, 2026 को 66वें 'गुजरात स्थापना दिवस' की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री का गुजरात स्थापना-गौरव दिवस के अवसर पर जनता के नाम संदेश इस प्रकार है :

मुख्यमंत्री ने गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी, सरदार साहब, स्वामी दयानंद सरस्वती और श्यामजी कृष्ण वर्मा के आशीर्वाद, तथा पूज्य रविशंकर महाराज और इंदु चाचा जैसे अनेक महापुरुषों की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के साथ-साथ लोगों के अहर्निश कठोर परिश्रम और सभी के सहयोग से गुजरात ने अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। आज उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि जब 1 मई, 1960 को गुजरात तत्कालीन मुंबई राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था, तब सभी के मन में यह सवाल था कि केवल रण (रेगिस्तान), समुद्र और पहाड़ों वाला यह राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन 1960 से 2000 तक चार दशकों की गुजरात की विकास यात्रा और वर्ष 2001 के बाद के ढाई दशकों की अविरत विकास यात्रा का बिल्कुल साफ और स्पष्ट अंतर आज हर कोई देख सकता है। गुजरात आज विकास की उस ऊंचाई पर है कि पूरी दुनिया गुजरात की ओर आकर्षित हो रही है। इसकी जड़ों में है श्री नरेन्द्र मोदी जैसा दूरदर्शी नेतृत्व, जो हमें मिला, साथ ही विकास की प्रति उनकी प्रतिबद्धता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी साहब ने गुजरात में विकास की राजनीति का युग विकसित किया। गुजरात उनकी प्रेरणा से आज देश के विकास का रोल मॉडल बन गया है। जनता-जनार्दन ने भी इस अविरत विकास यात्रा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए श्री मोदी साहब के नेतृत्व पर अपार विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है। उसी भरोसे और विश्वास को आप सभी ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में भी हमें प्रचंड समर्थन देकर बरकरार रखा है। हम नतमस्तक होकर आपके इस प्रेम का ऋण स्वीकार करते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए हर क्षेत्र में विकास की चरम सीमा को पार करके परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी है। प्रधानमंत्री ने बिजली, पानी, रोड नेटवर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करके इन सभी क्षेत्रों में आमूल बदलाव लाया है। आज 'ज्योतिग्राम योजना' के जरिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित गांवों को 24 घंटे निर्बाध थ्री-फेज बिजली मिल रही है। बिजली उत्पादन की क्षमता 8,750 मेगावाट से बढ़कर लगभग 53 हजार मेगावाट हो गई है। गुजरात देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड और विद्युत ग्रिड का निर्माण हुआ है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के साथ ही हमने शहरी विकास को और अधिक गति देने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया और शहरी विकास के बजट में 40 फीसदी का इजाफा किया। व्यापारी राज्य के रूप में जाने जाने वाले गुजरात में पूंजी निवेश को बढ़ाने और नए व्यापार-उद्योग विकसित करने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की।

वाइब्रेंट समिट की निरंतर सफलता के चलते गुजरात आज 'ग्लोबल गेट-वे टू दी फ्यूचर' और देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। हमारे हर जिले के अपने विशिष्ट उत्पाद और विशेष क्षमताएं हैं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमने इस क्षमता को 'वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म' देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) शुरू की है। उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र की ऐसी कॉन्फ्रेंस को शानदार सफलता मिली है, अब गुजरात स्थापना दिवस से सूरत में दक्षिण गुजरात क्षेत्र की वीजीआरसी का प्रारंभ हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि आज का जमाना सोलर, विंड और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन ग्रोथ का है। गुजरात ने तो बहुत पहले ही इस दिशा में आयोजन कर लिया है। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता देश की कुल क्षमता का 15 फीसदी हो गई है। सोलर रूफटॉप योजना में गुजरात तीन लाख से अधिक घरों को कवर करते हुए बहुत आगे निकल गया है।

इतना ही नहीं, पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर, हमने राज्य में हाईटेक इंडस्ट्रीज की स्थापना को वेग दिया है। राज्य में दो सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत हो गए हैं और दो अभी स्थापित होने जा रहे हैं। साणंद और धोलेरा सेमीकॉन इंडस्ट्री के हब बनने वाले हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उद्योगों को गति देने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है।

उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी उतनी ही अहम भूमिका है। नीति आयोग की मदद से सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों के रणनीतिक विकास के लिए सूरत इकोनॉमिक रीजन डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी ऐसे 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

हमने विकास के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 'अनिंग वेल, लिविंग वेल' पर फोकस करके 2047 के विकसित गुजरात का रोडमैप तैयार किया है। हमारा गुजरात ही देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ऐसा विशिष्ट विकास विजन तैयार किया है। 'अनिंग वेल और लिविंग वेल' की संकल्पना के साथ सतत विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास का हमारा लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण के जरिए ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ने 'मिशन लाइफ' की प्रेरणा दी है। इसके समर्थन में हमने बारिश के पानी के संचय के लिए 'कैच द रेन' का राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है।

हमने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधे लगाकर धरती माता को हरा-भरा बनाया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमितभाई शाह के सफल प्रयासों से गुजरात को 'कॉमनवेल्थ गेम्स' की मेजबानी करने का अवसर मिला है। हम इस कॉमनवेल्थ गेम्स के माध्यम से दुनिया का भारत की भूमि पर स्वागत करने और गुजरात को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश जब वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक विकसित भारत 2047 का आह्वान किया है। उन्होंने 2047 तक के इस समय को देश का अमृत काल कहा है। इस अमृत काल में गुजरात को तो अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर 2035 में अमृत महोत्सव का जश्न मनाने का एक बड़ा अवसर मिला है। वर्ष 2035 तक हमें गुजरात को दुनिया को विकास की दिशा दिखाने वाला मॉडल स्टेट बनाना है।

हमारा तो एक ही संकल्प है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, वंचितों और अदने व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और सभी जरूरतमंदों को आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य रक्षा कवच प्रदान करना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करके उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाकर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' मंत्र के माध्यम से गुजरात को विकास के हर क्षेत्र में नंबर वन बनाना।

आज गुजरात गौरव दिवस पर हम सभी साथ मिलकर 'विकसित भारत@2047' के लिए विकसित गुजरात का और गुजरात के विकास के लिए समर्पित होने का संकल्प करें। एक बार फिर, सभी को 'गुजरात गौरव दिवस' की अनेक अनेक शुभकामनाएं।

भारत माता की जय.. वंदे मातरम्..
जय जय गरवी गुजरात...

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अप्रैल-2026 के राज्य स्वागत कार्यक्रम में नागरिकों के प्रश्नों का समयसीमा में, न्यायिक और निष्पक्ष तरीके से समाधान करने के लिए सभी जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए

राज्य स्वागत कार्यक्रम की फलश्रुति

- किसान को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिलेगा
- वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी
- मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच आंतरिक समन्वय के अभाव में नागरिकों को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश दिए
- मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन सिस्टम की खामियों के कारण लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए निर्देश दिए
- मुख्यमंत्री ने अपनी टेबल से फाइल दूसरी टेबल पर जाने के बाद जिम्मेदारी पूरी मानने के बजाय; लोगों की समस्याओं का अंतिम समाधान होने तक जवाबदेही निभाकर समस्याओं का अंतिम निपटारा करने के निर्देश दिए

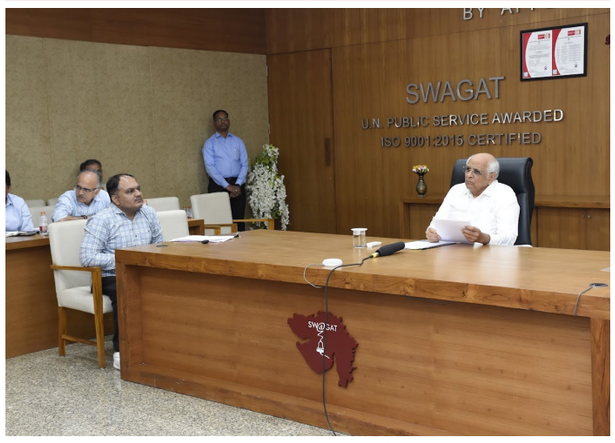

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अप्रैल-2026 के राज्य स्वागत कार्यक्रम में आई प्रस्तुतियों को प्रत्यक्ष रूप से सुनकर नागरिकों की समस्याओं का समयसीमा में, न्यायिक और निष्पक्ष तरीके से समाधान करने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए।

हर महीने आयोजित होने वाले स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम में अप्रैल-2026 के राज्य स्वागत में पूरे राज्य से 110 से अधिक प्रस्तुतकर्ता अपने प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित रहे। इतना ही नहीं; राज्य में जिला स्वागत के में कुल 1,335 प्रस्तुतियों पर आवश्यक कार्रवाई की गई।

पंचमहाल जिले में कृषि भूमि की बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आईओआरए पोर्टल में आवेदन किया था। इस आवेदन को अधिकारियों द्वारा एक-दूसरे को ट्रांसफर करते रहने के कारण प्रस्तुतकर्ता के आवेदन का लंबे समय तक निपटारा नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने गंभीर संज्ञान लिया। ऑनलाइन प्रणाली की खामी के कारण लोगों को परेशानी न हो, यह देखने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए।

भरूच जिले के झगडिया तहसील में करजण जलाशय योजना अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का अवॉर्ड मंजूर होने के बावजूद लंबे समय तक मुआवजा न मिलने पर किसान ने शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान को 10 दिनों के भीतर मुआवजा देने और भुगतान में देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने एक अन्य शिकायत में लोगों को नकली दस्तावेज दिखाकर वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आदेश दिए।

इसके अलावा; मुख्यमंत्री ने मेहसाणा जिले में रिसर्वे प्रोमल्गेशन में कृषि भूमि के क्षेत्रफल में हुए घटाव के लिए भूमि मापन और मापन के बाद रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए किसानों की सामूहिक प्रस्तुतियां मिलने पर किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए।

इस स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि अपने टेबल से फाइल दूसरे टेबल पर जाने से अपनी जिम्मेदारी पूरी मानने के बजाय, लोगों के प्रश्नों का अंतिम निपटारा होने तक जिम्मेदारी निभाते हुए, समस्याओं का अंतिम समाधान करना चाहिए।

अप्रैल-2026 के इस राज्य स्वागत में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अजय कुमार तथा विशेष कार्य अधिकारी श्री डी. के. पारेख, श्री राकेश व्यास, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर, एसपी और डीडीओ उपस्थित रहे।

सूरत वार्ड की राजनीति में विवाद: दिनेश राजपुरोहित और विजय चौमल पर गंभीर आरोप

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के वार्ड नंबर 18 से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले दिनेश राजपुरोहित को टिकट मिलने के बाद, उनका एक वीडियो/ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन्हें आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस लेने के लिए शर्म-दम-दंड-भेद की नीति अपनाते हुए सुना जा सकता है। इस वीडियो में उन्होंने लालच भरे शब्दों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष धमकियां भी दीं। इस प्रकार, दूसरी बार चुनाव का टिकट मिलते ही दिनेश राजपुरोहित आसमान छूने लगे। उनका व्यवहार लोकतंत्र के लिए कलंक है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो सत्ताधारी दल या उसके उम्मीदवार, चाहे वे किसी भी दल से चुनाव लड़ें, उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं, 28 अप्रैल को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, पराजित कांग्रेस उम्मीदवार खुमान सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जिस तरह से बेरहमी से हमला किया गया, वह लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं था। इस घटना को सोशल मीडिया पर भी खूब उछाला गया। यहाँ देखने लायक बात यह है कि दिनेश राजपुरोहित दूसरी बार चुने जाने के बाद किस हद तक तानाशाह बन गए हैं। एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो किसी भी पार्टी से चुनाव क्यों न लड़ा जाए? सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार इसका विरोध कैसे कर सकता है? एक तरफ भाजपा खुद को अनुशासित और कार्यकर्ता-आधारित पार्टी बताती है, जिसने अतीत में भय, भूख और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बड़ी-बड़ी बातें की थीं, वहीं दूसरी तरफ इसी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अपने गॉडफादरों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिनेश राजपुरोहित जैसे लोगों के लिए अपने गॉडफादरों की मर्जी से नेतृत्व करना उचित नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे समाज के लिए एक समान भावना के साथ जनता के लिए काम करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को कभी भी किसी के प्रति घृणा या दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। दिनेश राजपुरोहित जैसे मंदबुद्धि लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता जब किसी भी समुदाय का कोई व्यक्ति किसी बड़े नेता के पद पर पहुंचता है। वे किसी भी समुदाय के व्यक्ति की तरक्की को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका काम उस वार्ड के लोगों का है जहां से वे चुने गए हैं। उन्हें उनकी सेवा करनी है। जहां अवैध पार्किंग की समस्या है, उनके कार्यालय के 100 से 500 मीटर के दायरे में शराब और जुए के अड्डे चल रहे हैं, अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं और पुणे-पटिया कंगारू सर्कल में रविवार और गुरुवार को मेला लगता है, वहां दिनेश राजपुरोहित को यह दिखाई नहीं देता कि वहां के निवासी यातायात की समस्या से परेशान हैं। यह सब देखकर सिस्टम से उनकी (दिनेश की) मिलीभगत उजागर हो जाती है। इसलिए, दिनेश राजपुरोहित ने अपना चुनावी क्षेत्र छोड़ दिया है और रिंग रोड पर फोस्टा के कार्यालय में बैठकर पुरोहित थाली नाम से एक लॉज चला रहे हैं। उनका कपड़ा व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं है। अगर दिनेश बाज़ार के व्यापारियों को समझौता कराने और सलाबतपुरा पुलिस के साथ समझौता करने जैसे गैर-कानूनी काम कर रहा है, जो उसका काम नहीं है, तो उसने सूरत से राजस्थान तक अपने दो कार्यकाल में कितनी संपत्तियां बनाई होंगी? अगर इसकी भी जांच हुई तो बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन जांच कौन करेगा? सूरत शहर में सूरत एमएनपी के पदाधिकारियों के चुनाव में, ऐसे भाग्यशाली साधुओं ने अपने गुरुओं के ज़रिए शहर को और लूटने के लिए जगह पाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों को कोई भी ऊँचा पद मिल गया, तो वे शहर को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भ्रष्ट लोगों को सत्ता से दूर रखना चाहिए। विजय चौमल की मानसिकता ऐसी है मानो वह किसी गाड़ी के नीचे से बोझ खींच रहा हो। अब अगर हम वार्ड नंबर 19 की बात करें, तो विजय चौमल, जिनका टिकट रद्द कर दिया गया है, उस इलाके के लोगों से निजी तौर पर कहते थे कि अगर वार्ड नंबर 19 में विजय चौमल नहीं हैं, तो कोई और है ही नहीं और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए पर्दे के पीछे से दुष्प्रचार शुरू कर दिया था। विजय चौमल के आरएसएस के संरक्षकों ने उन्हें दो बार टिकट दिया था। हर बार विजय चौमल को आरएसएस से प्रोत्साहन मिलता रहा था।

लेकिन इस चुनाव में, विजय चौमल का टिकट काटे जाने के अलावा, ब्याज पर पैसे देते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया, और ब्याज पर पैसे लेने वाले को धमकी देते हुए विजय चौमल का ऑडियो भी वायरल हो गया। वहीं, रणछोड़ देवासी और हरीश चौधरी उनकी दुकान में साझेदार हैं। रणछोड़ देवासी ने ही विजय चौमल का परिचय हरीश चौधरी से कराया था। रणछोड़ देवासी के माध्यम से ही विजय चौमल साझेदार बने। और आज विजय चौमल करोड़ों रुपये कमा चुके हैं। वहीं रणछोड़ देवासी को पैसों की सख्त जरूरत थी। विजय चौमल से ब्याज सहित ली गई रकम चुकाने के बाद भी, विजय चौमल को परेशान किया गया और धमकी दी गई। यहां तक कि पुलिस के माध्यम से भी धमकियां दी गईं।

इससे पहले, निर्माण कार्य न करने के लिए विजय चौमाल के खिलाफ एसीबी में पांच लाख रुपये की रिश्वत की शिकायत भी दर्ज की गई थी। मामला अदालत में लंबित है। फिर, जब वार्ड नंबर 19 में चारों उम्मीदवार जीत गए, तो विजय चौमाल ने अपने राजनीतिक नेताओं की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मानो उन्होंने अपनी मेहनत से चुनाव जीता हो, और नेताओं के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाने और शेखी बघारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो खुलेआम ये कहता फिरता है कि अगर उसने मेरे खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज न कराई होती, तो आज मैं विधानसभा में मंत्री होता। इसलिए, गुजरात की टीम सूरत से लेकर राजस्थान तक, दो कार्यकालों में विजय चौमाल ने कितनी संपत्तियां बनाई हैं, इसकी गहन जांच करेगी और सच्चाई सामने लाएगी।

इस प्रकार, विजय चौमल जैसे बड़े नेता निगमों और समितियों में पद पाने के लिए ऐसे नेताओं की चापलूसी करने में भी शर्म महसूस नहीं करते। तो फिर आज की राजनीति कहां है, सुरेंद्रसिंह राजपूत और राज के. पुरोहित जैसे नेताओं की राजनीति कहां है? आज का समय दिखा रहा है कि राजनीति कितनी भ्रष्ट हो चुकी है।

गुजरात स्थापना दिवस पर जनसेवा की विरासत: प्रवासी नेताओं की निडर राजनीति को नमन

सूरत। 1 मई 1960 का दिन भारतीय संघीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है, जब भाषाई आधार पर पुनर्गठन के तहत Gujarat और Maharashtra का गठन हुआ। एक ओर गुजराती भाषी समाज को अपनी पहचान मिली, वहीं दूसरी ओर मराठी भाषी जनता को भी अपना अलग राज्य मिला। तब से हर वर्ष 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो न केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का भी उत्सव है। इस विशेष अवसर पर उन नेताओं को याद करना स्वाभाविक है, जिन्होंने अपनी निष्ठा, संघर्ष और जनसेवा के माध्यम से इस राज्य की राजनीति को नई दिशा दी। ऐसे ही एक नाम हैं Surendra Singh Rajput, जिन्हें उनकी निडरता, स्पष्टवादिता और जनहित के प्रति समर्पण के लिए आज भी याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश की धरती से निकलकर गुजरात की राजनीति में अपनी पहचान बनाना कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत ने यह कर दिखाया। वे उन चुनिंदा प्रवासी नेताओं में से थे, जिन्होंने न केवल स्थानीय राजनीति में जगह बनाई, बल्कि जनता के बीच गहरी पैठ भी बनाई। गुजरात विधानसभा की स्थापना के बाद उन्हें राज्य के पहले अनिवासी नेता के रूप में सदन में बैठने का अवसर मिला, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह केवल उनकी राजनीतिक क्षमता का ही प्रमाण नहीं था, बल्कि उस समय के सामाजिक समावेश और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उदाहरण था। राजपूत का राजनीतिक जीवन कॉलेज के दिनों से ही सक्रिय रहा। वे छात्र राजनीति में महासचिव के रूप में चुने गए और यहीं से उनके नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी। इसके बाद उन्होंने Ahmedabad Municipal Corporation में पार्षद के रूप में कार्य किया और जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को समझा। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें एक प्रभावशाली विधायक बनने में सहायक साबित हुआ। उन्होंने गुजरात विधानसभा में दो बार विधायक के रूप में जनता के मुद्दों को बेबाकी से उठाया और हर बार अपने निडर स्वभाव से सरकार को जवाबदेह बनाया। उनकी राजनीति का सबसे उल्लेखनीय पहलू था उनका साहस और जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। Navnirman Movement के दौरान जब पूरे गुजरात में युवा वर्ग आंदोलन कर रहा था, तब सुरेंद्र सिंह राजपूत उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने युवाओं के समर्थन में यह तक कह दिया था कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे खुद को जिंदा दफन कर देंगे। यह बयान उस समय की सरकार के लिए एक बड़ा झटका था और इससे यह स्पष्ट हुआ कि वे केवल शब्दों के नेता नहीं, बल्कि अपने विचारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।

1975 में उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश किया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने न केवल विधानसभा चुनाव लड़े, बल्कि लोकसभा तक अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने Madhavsinh Solanki और Amarsinh Chaudhary की सरकारों में विधायक के रूप में कार्य किया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की। उनकी कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण को Indian National Congress ने भी सराहा।

जब Rajiv Gandhi देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सुरेंद्र सिंह राजपूत ने गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक अनूठा अभियान चलाया। उन्होंने राज्य के दूरदराज के गांवों तक करीब दस हजार किलोमीटर की पदयात्रा की, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी।

प्रतापनगर- लालकुआँ के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा तथा यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने एवं अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल से प्रतापनगर – लालकुआँ स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09119/09120 प्रतापनगर – लालकुआँ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन(18 फेरे)

ट्रेन संख्या 09119 प्रतापनगर – लालकुआँ स्पेशल रविवार,को प्रतापनगर से शाम 17:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:45 बजे लालकुआँ पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 मई 2026 से 28 जून 2026 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09120 लालकुआँ - प्रतापनगर स्पेशल सोमवार को लालकुआँ से दोपहर 15:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:30 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन 04 मई 2026 से 29 जून 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, गंगापुर सिटी, भरतपुर जंक्शन, मथुरा जंक्शन, हाथरस सिटी, कासगंज जंक्शन, बहेड़ी जंक्शन और किच्छा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास, द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09119 की बुकिंग 02 मई 2026 को सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

डीआरएम अहमदाबाद ने एनआईडी का दौरा किया पार्सल ट्रॉली एवं रेलवे उपकरण डिज़ाइनों का किया निरीक्षण

मंडल रेल प्रबंधक (DRM), अहमदाबाद, वेद प्रकाश ने दिनांक 30 अप्रैल 2026 को National Institute of Design (एनआईडी), अहमदाबाद परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान के संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद किया तथा Indian Railways से संबंधित विभिन्न डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया।

रेलवे बोर्ड एवं एनआईडी, अहमदाबाद के संयुक्त सहयोग से वर्ष 2015 में स्थापित रेलवे डिज़ाइन सेंटर (RDC) भारतीय रेलवे में नवाचार को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों द्वारा विकसित डिज़ाइन समाधानों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यरत है। इस सहयोग को वर्ष 2025 में पुनः विस्तारित करते हुए वर्ष 2035 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

दौरे के दौरान डीआरएम ने पार्सल प्रबंधन, स्टेशन संचालन एवं यात्रियों की सुविधा से जुड़े विभिन्न डिज़ाइन समाधानों का निरीक्षण किया। विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर विकसित पार्सल ट्रॉली एवं संबंधित उपकरणों के डिज़ाइन प्रस्तुत किए गए, जिनमें आधुनिक स्वरूप, उपयोग में सरलता तथा लोडिंग-अनलोडिंग प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन ट्रॉली डिज़ाइनों का उद्देश्य पार्सल को प्लेटफॉर्म से पार्सल वैन तक सुगमता से पहुँचाना तथा कोच में लोडिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस अवसर पर डीआरएम वेद प्रकाश ने कहा कि एनआईडी द्वारा विकसित ये डिज़ाइन रेलवे स्टेशनों पर कार्यकुशलता बढ़ाने, पार्सल प्रबंधन को बेहतर बनाने तथा प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ की समस्या को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते है। 01.05.2026 को एनआईडी द्वारा निर्मित पार्सल ट्रॉली का अहमदाबाद स्टेशन पर रेल अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

यह पहल दर्शाती है कि तकनीकी एवं डिज़ाइन संस्थान वास्तविक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यह दौरा रेलवे बोर्ड एवं एनआईडी के बीच सुदृढ़ सहयोग तथा उपयोगकर्ता-केंद्रित, भविष्य उन्मुख समाधान विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करता है। रेलवे डिज़ाइन सेंटर (RDC) के माध्यम से भारतीय रेलवे में नवाचार को नई दिशा देने एवं यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।